संक्षिप्त

कादरी होंगे शहर कांग्रेस अल्पसंख्यक संगठन महासचिव

बीकानेर (निसं)। कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष अकबर अली खादी ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष (अल्पसंख्यक) इमरान प्रतापगढ़ी की अनुशंसा पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष (अल्पसंख्यक) एम डी चौबदार ने शहर जिला कांग्रेस (अल्पसंख्यक) बीकानेर के पदाधिकारीयों की सूची जारी कर दी। जिसमें एन डी कादरी को संगठन महासचिव बनाया गया। चार ब्लॉक अध्यक्ष शाहबुद्दीन भुट्टा, यकिनूद्दीन डग्गा, एडवोकेट सैयद इशाक अली , फ़रमान कायमखानी के साथ ही करतारसिंह , ऐजाज़ पठान, अहमद अली भाटी, उस्मान गनी सहित आठ उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। गौतम कोचर, मोहम्मद हुसैन खिलजी सहित 17 महासचिव बनाए गए हैं। मोहम्मद हुसैन पप्पू प्रवक्ता अलीरज्जा मिडिया प्रभारी होंगे। इसके अलावा 19 सचिव व 13 संयुक्त सचिव भी बनाए गए हैं। व एक कोषाध्यक्ष होगा अकबर अली खादी ने अपनी कार्यकारिणी में पूर्व पश्चिम दोनों विधानसभाओं से कर्मठ निष्ठावान कांग्रेस समर्पित कार्यकर्ताओं को ही साथ लेकर चलने के संकल्प के आधार पर कार्यकारिणी बनाई गई है।

'एक शाम कैफ़ी आज़मी तलत महमूद के नाम'

बीकानेर(निसं)। सुर गंगा म्यूजिकल ग्रुप बीकानेर द्वारा आगामी 9 मई को महाराजा नरेंद्रसिंह ऑडिटोरियम होटल लाल जी के सामने शाम 5 बजे हिंदी सिनेमा के जाने-माने गीतकार कैफ़ी आज़मी की 24 वी व पार्श्वगायक तलत महमूद की 28 वी पुण्यतिथि के अवसर पर रंगारंग फिल्मी गीतों का कार्यक्रम एक शाम कैफ़ी आज़मी तलत महमूद के नाम आयोजित किया जाएगा संस्था अध्यक्ष एम रफीक कादरी ने बताया कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एन डी रंगा अध्यक्ष सखा संगम होंगे अध्यक्षता एम आर मुगल करेंगे विशिष्ट अतिथि रहमत अली महबूब रंगरेज कांग्रेस नेता मो सदीक चौहान होंगे । कार्यक्रम में गीतकार कैफ़ी आज़मी के लिखे गीत व पार्श्वगायक तलत महमूद के गाए गीत ग्रुप के सदस्य पेश करेंगे कार्यक्रम का संचालन एम रफीक कादरी करेंगे।

लोगों तक पहुंचाई योजनाओं की जानकारी

बीकानेर। मुख्यमंत्रीभजन लाल शर्मा के निर्देश पर गांव-गांव तक प्रदेश सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंचाने और 23 मई से जयपुर में होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट (ग्राम) के महत्त्व से अवगत करवाने के लिए जिले में 28 अप्रैल से चल रहा 'ग्राम रथ अभियान' ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रभावी पहल बन गया है। अभियान के पहले सात दिनों में जिले की 189 ग्राम पंचायतों के 60 हजार से अधिक महिलाओं और पुरूषों तक सरकार की योजनाओं की जानकारी पहुंची है। अनेक लोगों को मौके पर इन योजनाओं का लाभ मिला है। यह अभियान 12 मई तक अनवरत चलेगा तथा जिले के प्रत्येक ग्राम पंचायत तक पहुंचकर इन रथों द्वारा सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। 'ग्राम रथ अभियान' के प्रति गांव-गांव में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं मंगल गीत गाकर इन रथों का स्वागत कर रही हैं। कला-जत्थों की प्रस्तुतियों ने इसे उत्सव का रूप दे दिया है। इन जत्थों के कलाकार पारम्परिक और सरल तरीकों से सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। वहीं अभियान के तहत अब तक सभी संबंधित 13 विभागों के 1 लाख 31 हजार से अधिक पेम्प्लेट्स का वितरण करते हुए योजनाओं के बारे में बताया गया है। जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी इसे और अधिक खास बना रही है।
पांचों विधानसभाओं में प्रतिदिन संध्या चौपाल का आयोजन हो रहा है।

अधिकारियों की हठधर्मिता ने अदालतों पर लादा 15600 मुकदमों का बोझ

■ **विभागीय संवेदनहीनता का आलम यह है कि कर्मचारी अपने ही पूर्व साथियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान कर रहे हैं।**

बीकानेर (निसं)। शिक्षा विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और 'चढ़ावे' की संस्कृति ने प्रदेश के सबसे बड़े महकमे को कानूनी मकड़जाल में उलझा दिया है। फाइलों को अटकाने की प्रवृत्ति के कारण न्यायिक वादों का ग्राफ इतना बढ़ गया है कि विभाग में औसतन हर 60 शिक्षकों पर एक कोर्ट केस दर्ज है। वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के 8,000 और माध्यमिक के 7,600 मामलों को मिलाकर कुल 15,600 केस अदालतों में लंबित हैं। इनमें से 40 फीसदी मामले महज अफसरों की हठधर्मिता और व्यक्तिगत स्वार्थ की भेंट चढ़े हैं।

विभागीय संवेदनहीनता का आलम यह है कि कर्मचारी अपने ही पूर्व साथियों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए परेशान कर रहे हैं। लूणकरणसर के एक मृतक आश्रित को अब तक नौकरी मिल जाती, यदि प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जीएडी अनुभाग ने नकारात्मक टिप्पणी न की होती। केवल सुविधा शुल्क की लालसा में फाइल को ऊपर भेज दिया गया और जयपुर में बैठे अधिकारियों ने भी बिना सोचे-समझे उसे अपील में डाल दिया। वर्तमान में माध्यमिक निर्देशालय में दो दर्जन और प्रारंभिक में करीब एक दर्जन मृतक आश्रितों के मामले सिर्फ इसलिए लंबित हैं क्योंकि कर्मचारी खुद नहीं चाहते कि उन्हें नौकरी मिले। स्थिति यह है कि अदालती आदेशों की पालना भी तब तक नहीं होती, जब तक कोर्ट अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से तलब न कर ले।

शिक्षा सेवा नियमों में बार-बार बदलाव और डीपीसी (विभागीय पदोन्नति समिति) की लंबी प्रक्रिया ने शिक्षकों में हताशा पैदा कर दी है। स्नातक में एडिशनल विषय को लेकर तृतीय श्रेणी से द्वितीय श्रेणी पदोन्नति का मामला पिछले पांच साल से न्यायालय में लंबित है। इसके चलते स्कूलों में कक्षा 9 व 10 को पढ़ाने वाले सेकंड ग्रेड शिक्षकों के हजारों पद खाली पड़े हैं, जिसका सीधा खामियाजा ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थी भुगत रहे हैं। विभाग की कार्यप्रणाली ऐसी है कि न्यायालय के आदेशों के बावजूद उनकी पालना नहीं की जाती। नतीजा यह है कि शिक्षा निर्देशक और शिक्षा सचिव के खिलाफ शिक्षकों ने दर्जनों अवमानना के मामले लगा रखे हैं। मौजूदा निदेशक दर्जनों बार कोर्ट में पेश हो चुके हैं। 2021 में सुप्रीम कोर्ट तक ने राजस्थान के शिक्षा अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया था लेकिन इसके बावजूद प्रशासनिक ढर्रे में कोई बदलाव नहीं आया।

शिक्षक राजितराम के निधन (1996) के बाद उनके पुत्र सुनील ने बालिग होने पर 2004 में अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन किया। विभाग ने फाइल को 11 साल तक लटकाए रखा, जिसके विरुद्ध सुनील ने 2015 में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 9 साल की कानूनी लड़ाई के बाद 16 मार्च 2024 को एडीजे कोर्ट ने विभाग को 90 दिन के भीतर नौकरी देने या रिट लगाने का आदेश दिया। आदेश के सवा दो साल बाद भी विभाग ने न तो नियुक्ति दी और न ही समय पर रिट दाखिल की। अपनी गलती सुधारने के बजाय विभाग अब मामले को खींचने के लिए दोबारा रिट लगाने की तैयारी कर रहा है। यह मामला विभाग की चरम संवेदनहीनता और अदालती आदेशों के प्रति ढीठाई का स्पष्ट उदाहरण है। चूरू जिले का एक मामला विभाग की मेजों पर धूल फांकती फाइलों की कहानी बयां करता है। प्रबोधक पद के लिए एक मृतक आश्रित ने समय पर आवेदन किया लेकिन नीचे के कर्मचारियों ने फाइल आगे नहीं बढ़ाई। जब मामला ऊपर पहुंचा, तो उसे समय बीतने का हवाला देकर खारिज कर दिया गया। एक दशक तक यह मामला फाइलों में दबा रहा। हालांकि उच्च अधिकारियों ने माना कि फाइल विभाग में ही अटकी थी इसलिए नौकरी दी जानी चाहिए लेकिन खाऊ कर्मचारियों ने फिर भी अड़ंगा लगाया। जैसे ही पीड़ित महिला ने कोर्ट में रिट लगाई तो जो फाइल 10 साल से नहीं हिली थी उस पर चंद दिनों में ही आदेश जारी हो गए। अनुकंपा नियुक्ति कोई मौलिक अधिकार या विरासत नहीं, बल्कि पीडति परिवार को तुरंत राहत देने हेतु सरकार की एक विशेष सहानुभूति है। न्यायालयों ने भी स्पष्ट किया है कि इसके नियम लचीले होने चाहिए ताकि आश्रितों को दफ्तरों के धक्के न खाने पड़ें। विडंबना यह है कि विभाग इस उद्देश्य के उलट मृतक आश्रितों से 15-15 स्टाम्प और शपथ पत्र मांगकर प्रक्रिया को जटिल बना रहा है। स्पष्ट पहचान होने के बावजूद, आवेदन में कुछ दिनों की देरी जैसे तकनीकी कारणों के चक्कर में आवेदकों के 15 से 20 साल खराब किए जा रहे हैं।

अवैध शराब की 16 भट्ठियां तोड़ी

■ **11 हजार लीटर से ज्यादा लाहन किया नष्ट, 25 केस दर्ज**

हनुमानगढ़ (निसं)। यहां अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग ने कार्रवाई की है। एक विशेष अभियान के तहत जिले में हजारों लीटर लाहन नष्ट किया गया और कई कच्ची भट्ठियों को ध्वस्त किया गया। यह अभियान आबकारी आयुक्त के निर्देश पर 1 से 15 मई तक चलाया जा रहा है।

इसी के तहत मंगलवार को संयुक्त टीम ने गगागढ़, गंगाघाट, देबूघाट और श्रीनगर सहित कई क्षेत्रों में दबिश दी। इस दौरान लगभग 4500 लीटर लाहन मौके पर ही नष्ट किया गया और 8 कच्ची भट्ठियों को तोड़ा गया। इस कार्रवाई में अवैध शराब के 2 प्रकरण दर्ज किए गए और 60 लीटर हथकढ़ शराब भी बरामद की गई।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार इस अभियान के तहत अब तक जिलेभर में कुल 11450 लीटर लाहन नष्ट किया जा चुका है। साथ ही 16 कच्ची भट्ठियों को ध्वस्त किया गया है। कुल 25 प्रकरण दर्ज किए गए हैं और एक बाइक भी जब्त की गई है।

आबकारी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अवैध शराब के निर्माण और बिक्री पर पूरी तरह रोक लगाने के लिए लगातार छापेमारी और गश्त की जा रही है। विभाग उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे रहा है, जहां पहले भी अवैध शराब निर्माण की गतिविधियां सामने आती रही हैं।

इस अभियान में हनुमानगढ़ प्रहराधिकारी अमर सिंह, भादरा प्रहराधिकारी विरेंद्र सिंह, नोहर प्रहराधिकारी कमल सिंह, संगरिया प्रहराधिकारी विनोद कुमार और हुसैन खान सहित आबकारी विभाग की टीमें शामिल रहीं।

जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने जानकारी दी कि चालू वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 92 प्रकरण दर्ज किए जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

तीन राज्यों में भाजपा की जीत पर अरजनसर में जश्न

■ **कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर व आतिशबाजी कर जताई खुशी**

अरजनसर (निसं)। अरजनसर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तीन राज्यों के चुनाव परिणामों के बाद पार्टी की जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटीं और आतिशबाजी की।

कार्यकर्ताओं ने पश्चिम बंगाल, पुडुचेरी और असम में भाजपा की सरकार बनने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को 'कार्यकर्ता की जीत' बताते हुए इसे संगठन की मेहनत का परिणाम करार दिया।

भाजपा नेता शिवरतन शर्मा ने कहा कि यह जीत देश की जनता के विश्वास और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का परिणाम है। उन्होंने इसे कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का फल बताया और कहा कि यह जीत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी तथा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को आगे बढ़ाने का प्रतीक है। इस अवसर पर वार्ड पंच पूर्णाराम सारस्वत, मदन मोट, लक्ष्मीनारायण ओझा, प्रहलाद स्वामी, साहबराम, नरेश कुमार और गिरधारी लाल सहित कई भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे।

छात्रों को बाल विवाह, घरेलू हिंसा पर जागरूक किया

नोखा (निसं)। नोखा में बाल विवाह और घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। तालुका विधिक सेवा समिति नोखा द्वारा आयोजित इस शिविर में स्कूली विद्याथिर्यों को कानूनों की जानकारी देकर उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया गया।

यह कार्यक्रम राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बीकानेर के निर्देशानुसार आयोजित हुआ। शिविर का संचालन तालुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष लीलूराम सिहाग के मार्गदर्शन में किया गया।

कार्यक्रम के तहत राजकीय राठी उच्च माध्यमिक विद्यालय और आदर्श राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय, नोखा के कक्षा 8 से 12वीं तक के विद्याथिर्यों को संबोधित किया गया। उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम और घरेलू हिंसा से संबंधित कानूनों की विस्तृत जानकारी दी गई।

पैनल अधिवक्ता विजय प्रताप सिंह राठौड़ ने छात्रों को बताया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है, जो बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालता है। उन्होंने विद्याथिर्यों से अपील की कि यदि उन्हें अपने आसपास कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले, तो वे तुरंत प्रशासन या हेल्पलाइन पर इसकी सूचना दें।

तालुका विधिक सेवा समिति के सचिव ओमप्रकाश देवड़ा ने घरेलू हिंसा के विभिन्न रूपों पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्पष्ट किया कि शारीरिक उत्पीड़न के साथ-साथ मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न भी घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। देवड़ा ने महिलाओं और बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। पैरा लीगल वॉलिंटियर साहिल खान ने विद्याथिर्यों को कानूनी सहायता प्राप्त करने के तरीकों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जरूरतमंद व्यक्ति निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

विक्रेताओं को दी जाए कृषि तकनीकों की जानकारी

बीकानेर, 5 मई। कृषि विज्ञान केंद्र, बीकानेर में उर्वरक विक्रेताओं हेतु 15 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम मंगलवार से प्रारम्भ हुआ। उद्घाटन अवसर पर मुख्य अतिथि के रुप में कुल गुरु डॉ. आर.बी. दुबे ने संतुलित उर्वरक उपयोग की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि अंधाधुंध उर्वरक उपयोग से मृदा की उर्वरता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उन्होंने मृदा परीक्षण आधारित उर्वरक उपयोग करने की सलाह दी। डॉ दुबे ने कहा कि उन्नत एवं क्षेत्र विशेष के अनुकूल बीज किस्मों का चयन उत्पादकता व गुणवत्ता में उल्लेखनीय वृद्धि लाने में सक्षम है। अच्छा बीज ही अच्छी फसल की नींव है। प्रसार शिक्षा निदेशक डॉ. दीपाली धवन ने कृषि विस्तार तंत्र की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा कि उर्वरक विक्रेता किसानों और वैज्ञानिकों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। उर्वरक विक्रेताओं को वैज्ञानिक जानकारी होने से वे किसानों को सही समय पर , सही सलाह देकर उत्पादन बढ़ाने में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से अपडेट रहने तथा नई तकनीकों को अपनाने पर विशेष बल दिया। कृषि विज्ञान केंद्र, बीकानेर- के प्रधान वैज्ञानिक डॉ. मदन लाल रेगर ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि 15 दिवसीय प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को मृदा परीक्षण की विधियाँ, उर्वरकों का संतुलित उपयोग, पोषक तत्व प्रबंधन, उर्वरकों का सुरक्षित भंडारण, गुणवत्ता नियंत्रण, कीट एवं रोग प्रबंधन तथा आधुनिक कृषि तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। प्रशिक्षण में प्रायोगिक सत्र भी शामिल किए गए हैं, जिससे प्रतिभागी व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। सहायक आचार्य डॉ. सुशील कुमार ने बागवानी फसलों में पोषक तत्व प्रबंधन पर विस्तृत जानकारी दी। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, बीकानेर के डॉ. एम.के. जाटव ने मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन विषय पर जानकारी साझा की तथा सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के प्रभावों के बारे में बताया।

बीकानेर : आरजीएचएस में इलाज बंद होने पर भड़का आक्रोश

बीकानेर (निसं)। प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के चिकित्सा अधिकारों पर आए संकट को लेकर अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने सरकार के खिलाफ आर-पार की जंग का ऐलान कर दिया है। रविवार को जयपुर के चौड़ा रास्ता स्थित श्री गोवर्धननाथ जी मंदिर परिसर में आयोजित महासमिति एवं जिलाध्यक्षों की संयुक्त बैठक में चिकित्सा मंत्री के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन का निणर्य लिया गया।

महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष महावीर शर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि आरजीएचएस योजना के तहत इलाज और दवाइयां बंद होना चिकित्सा विभाग की गंभीर प्रशासनिक विफलता है, जिसके लिए सीधे तौर पर चिकित्सा मंत्री उत्तरदायी हैं। बैठक में मौजूद बीकानेर जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज लेघा ने बताया कि 25 मार्च से दवाइयां और 14 अप्रैल 2026 से संपूर्ण इलाज बंद होने के कारण कर्मचारी दर-दर भटक रहे हैं। अब तक प्रदेश के कर्मचारियों की जेब से इलाज के नाम पर लगभग 300 करोड़ रुपये लग चुके हैं। सरकार की एक माह से जारी चुप्पी उसकी असंवेदनशीलता को दर्शाती है।

जिला मंत्री मनोज सुथार ने बताया कि कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा के लिए महासंघ ने आंदोलन की रूपरेखा तैयार की है। प्रथम चरण में 04 मई को मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी गई।

द्वितीय चरण में 12 मई को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर हजारों कर्मचारी चिकित्सा मंत्री का पुतला दहन करेंगे। तृतीय चरण में 15-25 मई तक चिकित्सा मंत्री के प्रत्येक राजकीय दौरे का क्षेत्रीय कर्मचारी बहिष्कार करेंगे और काले झंडे दिखाकर विरोध जताएंगे। चतुर्थ चरण में 28 मई को जयपुर में प्रदेश स्तरीय विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा।

बैठक में कर्मचारियों के सामाजिक और निजी जीवन पर हो रहे प्रहार का मुद्दा भी गूंजा। महासंघ ने रोष जताया कि पिछले 3 वर्षों से शनिवार-रविवार और अन्य राजकीय अवकाशों पर शिविरों या अभियानों में ड्यूटी लगाकर छुट्टियां छीनी जा रही हैं। इसके विरोध में 9 मई से शनिवार-रविवार के दिन कोई भी कार्य नहीं करेंगे।

निजी अस्पतालों और दवा विक्रेताओं (फार्मेसी) का सरकार पर करोड़ों का बकाया लंबे समय से विवाद की जड़ रहा है। पहले भी हुआ इलाज बंद: इससे पहले भी कई बार भुगतान में देरी के चलते निजी अस्पतालों ने इलाज बंद करने की चेतावनी दी थी, लेकिन इस बार 14 अप्रैल से जारी गतिरोध ने हजारों गंभीर मरीजों (कैंसर, डायलिसिस और हार्ट पेशेंट) की जान जोखिम में डाल दी है।सहकारी उपभोक्ता भंडारों और निजी मेडिकल स्टोर्स के भुगतान अटकने से 25 मार्च से ही कैशलेस दवाइयां मिलना बंद हो गई थीं।

विद्यालय को दीं कुर्सियां व वाटर सेंसर

बीकानेर(निसं)। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, पवनपुरी दक्षिण विस्तार में मंगलवार को एक सादे समारोह के बीच पूर्व प्राचार्या श्रीमती योगिता व्यास ने विद्यालय के प्रति अपना लगाव प्रदर्शित करते हुए कार्यालय उपयोग हेतु विभिन्न सामग्री भेंट की। भामाशाह श्रीमती व्यास ने विद्यालय की आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए कार्यालय सुसज्जित करने के लिए एक शानदार रिवॉल्विंग कुर्सी (प्राचार्य हेतु), 6 ऑफिस कुर्सियां और स्टाफ के लिए 5 लीटर का आधुनिक वाटर सेंसर विद्यालय को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विद्यालय मेरा परिवार रहा है और इसकी भौतिक आवश्यकताओं को पूरा करना मेरा सौभाग्य है।

बार एसोसिएशन, बीकानेर ने एस.पी. को ज्ञापन सौंपा

बीकानेर (निसं)। बार एसोसिएशन, बीकानेर द्वारा अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित के नेतृत्व में आज जिला पुलिस अधीक्षक,मृदुल कच्छावा बीकानेर को जिला न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया।

ज्ञापन में अवगत कराया गया कि जिला न्यायालय बीकानेर में विभिन्न तारीखों पर असामाजिक तत्वों एवं खतरनाक अपराधियों का आवागमन निरंतर बना रहता है। साथ ही हाल ही में न्यायालय भवन को उड़ाने की धमकियां भी प्राप्त हुई हैं, जिससे अधिवक्ताओं, न्यायिक अधिकारियों एवं आमजन में भय का वातावरण बना हुआ है। इसके अतिरिक्त न्यायालय परिसर एवं आसपास के क्षेत्र में यातायात व्यवस्था भी अत्यधिक प्रभावित रहती है, जिससे कार्य में बाधा उत्पन्न होती है।

बार एसोसिएशन ने मांग की कि न्यायालय समय के दौरान परिसर में पर्याप्त संख्या में सशस्त्र गार्ड तैनात किए जाएं अथवा गश्त लगवाई जाए तथा नए व पुराने न्यायालय परिसर में यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने हेतु उचित प्रबंध किए जाएं। बार अध्यक्ष अजय कुमार पुरोहित द्वारा पुलिस अधीक्षक बीकानेर के द्वारा नशे के विरुद्ध चलाये जा रहे ऑपरेशन नीलकंठ के लिये भी धन्यवाद प्रेषित किया गया तथा बताया कि ऑपरेशन नीलकंठ के द्वारा नशे पर किये गये प्रहार से बीकानेर के युवाओं के भविष्य एवं सेहत पर सकारात्म प्रभाव पडेगा।

इस अवसर पर सचिव हेमंत सिंह, उपाध्यक्ष लेखराम धत्तरवाल, पूर्व अध्यक्ष रघुवीर सिंह, भंवर लाल बिश्नोई, सुखदेव व्यास, रूपेंद्र सिंह, रामनिवास विश्नोई, ताराचंद उपाध्याय, मनीष सांखला सहित अनेक अधिवक्ता उपस्थित रहे।

देशनोक में मुख्य मार्ग स्थित सुलभ शौचालय बदहाल

देशनोक (निसं)। कस्बे में मुख्य मार्ग पर स्थित एक सुलभ शौचालय बदहाल स्थिति में है। करणी मंडल के सामने और अस्पताल के पास होने के बावजूद, इसकी नियमित सफाई नहीं हो रही है, जिससे यह गंदगी का अड्डा बन गया है।

लंबे समय से सफाई न होने के कारण शौचालय में गंदगी का अंबार लगा हुआ है और आसपास दुर्गंध फैल रही है। यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुख्य मार्ग पर स्थित है और पास में अस्पताल होने के कारण यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में मरीजों और आमजन का आवागमन रहता है। स्थानीय दुकानदार प्रमोद उपाध्याय ने बताया कि शौचालय की सफाई काफी समय से नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि यह मार्ग मरीजों और राहगीरों के लिए प्रमुख रास्ता है, लेकिन नगर पालिका इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है।

स्थानीय नागरिकों ने शौचालय की खराब स्थिति पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और संक्रमण फैलने का खतरा भी बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से तत्काल सफाई व्यवस्था सुधारने और नियमित निगरानी रखने की मांग की है।

पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर प्रतिबंध

■ **आदेश का उलुंघन करने पर दोषी पर प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही होगी**

श्रीगंगानगर (निसं)। जिले से लगने वाले पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी इलाके में लगे मोबाईल टॉवरों का नेटवर्क भारतीय सीमा के अन्दर 3-4 किलोमीटर तक आने की सम्भावना है। फलस्वरूप राष्ट्रीय सुरक्षा पर आशांकित खतरे के दृष्टिगत पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने पर जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर डॉ. अमित द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है।

जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश दिया गया है कि श्रीगंगानगर जिले के किसी भी क्षेत्र, जहां से पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग से एवं पाकिस्तानी नेटवर्क के जरिये सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है, में कोई भी व्यक्ति पाकिस्तानी लोकल सिम का उपयोग नहीं करेगा। न ही किसी व्यक्ति को पाकिस्तानी लोकल सिम के उपयोग करने की अनुमति दी जावेगी। इस आदेश का उलुंघन करने पर दोषी व्यक्ति के विरूद्ध विधि के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। उक्त आदेश 15 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

रेंज में गैंगस्टर, एनडीपीएस व अवैध शराब की तस्करी करने वालों के पीछे पुलिस

बीकानेर (निसं)। यहां रेंज में गैंगस्टर, एनडीपीएस और अवैध शराब की तस्करी करने वालों पर सख्ती और उन्हें सलाखों के पीछे डालने में जुटेगी चारों जिलों की पुलिस। इसके लिए चारों जिलों के एसपी प्लान बनाकर काम करेंगे।

बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों की पुलिस गैंगस्टर के पीछे पड़ेगी। गैंग और उससे जुड़े लोगों को चिह्नित कर लिया गया है। अब उन्हें सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसके अलावा मादक पदार्थ और शराब की तस्करी करने वालों और उनके संपर्क में रहे लोगों पर भी सख्ती बरती जाएगी। बीकानेर रेंज के आईजी ओमप्रकाश ने चारों जिलों के एसपी से कहा है कि गैंग खत्म होनी चाहिए। गैंगस्टर को गिरफ्तार करो।

वे बाहर नहीं रहने चाहिए। इसके अलावा मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल लोगों पर सख्ती बरती जाए। बीकानेर और श्रीगंगानगर बॉर्डर एरिया में पूरी तरह सतर्क रहें। बॉर्डर पार से तस्करी में जुड़े स्थानीय लोग पर सख्ती बरतें। डिलिवरी लेने आने वालों को पकड़े। उनके आकाओं तक पहुंचे और पकड़कर जेल पहुंचाएं। हरियाणा-पंजाब से शराब की तस्करी रोकें। तस्करी में शामिल सरगनाओं तक पहुंचे।

पुलिस मुख्यालय की प्राथमिकताओं के साथ ही ये तीनों काम प्रभावी तरीके से करना होगा। आईजी ने सोमवार को बीकानेर रेंज के चारों जिलों के एसपी की क्राइम मीटिंग ली और दिशा-निर्देश दिए। इस दौरान अपराध और कानून-व्यवस्था की जानकारी ली। मीटिंग में बीकानेर एसपी मृदुल कच्छावा, श्रीगंगानगर एसपी हरिशंकर, हनुमानगढ़ एसपी नरेन्द्र मीणा और चूरू एसपी निश्चय प्रसाद मौजूद थे। मीटिंग में बताया गया कि दो माह में 34 गैंगस्टर पकड़े गए और आबकारी के 750 मुकदमे दर्ज किए गए हैं।

आईजी के निर्देश - अगर कोई मुल्जिम पोक्सो और एनडीपीएस में बरी होता है तो उसके खिलाफ अपील की जानी चाहिए। मुल्जिम अगर फरार है तो नए प्रावधानों में उनकी गैर हाजिरी में कोर्ट में ट्रायल कराएं। अगर किसी मुल्जिम की गिरफ्तारी पर कोर्ट से रोक है तो भी कोर्ट में चालान किया जा सकता है। इस पर काम करें।

अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी

श्रीगंगानगर (निसं)। भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से घुसपैठ एवं राष्ट्रविरोधी गतिविधियों से जन-सुरक्षा एवं शान्ति भंग की आशंका होने व राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिगत जिला मजिस्ट्रेट श्रीगंगानगर डॉ. अमित यादव द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपखण्ड श्रीगंगानगर, श्रीकरणपुर, पदमपुर, रायसिंहनगर, अनूपगढ व घडसाना से लगती हुई भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर पट्टी में प्रतिबन्धात्मक आदेश जारी किए गए हैं।

आदेश के अनुसार सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति आवागमन नहीं कर सकेगा। यदि किसी कृषक को अपनी कृषि भूमि में सिंचाई व्यवस्था के लिए जाना अनिवार्य हो तो वह उस क्षेत्र में स्थित सीमा सुरक्षा बल के बोर्डर पोस्ट अधिकारी, सेना के अधिकारी से अनुमति प्राप्त कर आवागमन कर सकेगा। सायं 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक उक्त क्षेत्र में कोई व्यक्ति तेज प्रकाश एवं तेज ध्वनि यंत्रों का उपयोग नहीं करेगा एवं पटाखे, बैंण्ड, डीजे इत्यादि नहीं चलायेगा। यह प्रतिबन्ध राज्य/केन्द्र सरकार के कर्मियों पर प्रभावी नहीं रहेगा। आदेश 15 सितम्बर 2026 तक प्रभावी रहेगा।

नवजात शिशु फोटोथैरेपी मशीन

हनुमानगढ़ । जंक्शन में लाल चौक के पास स्थित कैनाल कॉलोनी सीएचसी में अब नवजात शिशुओं को भर्ती कर पीलिया का उपचार किया जा सकेगा। इसके लिए फोटोथेरेपी मशीन की सुविधा प्रारंभ कर दी गई है। यह मशीन जिला अस्पताल से उपलब्ध करवाकर चिकित्सालय में स्थापित की गई है, जिससे अब क्षेत्र के नवजात शिशुओं को उपचार के लिए अन्यत्र रेफर करने की आवश्यकता में कमी आएगी।

फोटोथेरेपी मशीन से शिशु के शरीर में बढ़े बिलीरुबिन स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है। पूर्व में इस प्रकार के मामलों में नवजात शिशुओं को जिला अस्पताल या अन्य बड़े केंद्रों पर रेफर करना पड़ता था, जिससे अब राहत मिलेगी और यहीं पर उपचार मिल सकेगा। प्रभारी- स्टाफ को किया ट्रेंड, नवजात शिशुओं की होगी नियमित निगरानी: कैनाल कॉलोनी चिकित्सालय प्रभारी डॉ. इन्द्रसेन झाझड़ा ने बताया कि फोटोथेरेपी मशीन को संचालित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली गई हैं।

स्टाफ को भी इसके संचालन के लिए प्रशिक्षित किया गया है। नवजात शिशुओं की नियमित निगरानी एवं देखभाल के लिए आवश्यक प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। सीएमएचओ-नवजात शिशु मृत्यु दर में आएगी कमी, समय पर मिलेगा उपचार: सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा का कहना है कि जिला अस्पताल से फोटो थैरेपी मशीन सीएचसी में स्थापित करवाई गई है। यह मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जिससे जिले में नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाने में भी सहायता मिलेगी। विधायक- चिकित्सा मंत्री के समक्ष रखेंगे समस्या: क्षेत्रीय विधायक गणेशराज बंसल का कहना है कि डॉक्टर्स की नियुक्ति के साथ ही सीएचसी में आवश्यक सुविधाएं बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए चिकित्सा मंत्री के समक्ष समस्या रखकर समाधान करवाया जाएगा। स्थानीय स्तर पर हल होने वाली समस्या के लिए सीएमएचओ को निर्देशित किया जाएगा ताकि मरीजों को किसी तरह की असुविधा नहीं हो। भाजपा नेता- सुविधा विस्तार के लिए करेंगे प्रयास: भाजपा नेता अमित सहू का कहना है कि जंक्शन सीएचसी में मरीजों को किसी तरह की समस्या नहीं आए।